एम.एम.एस. निवेश, मदुरै और अन्य

बनाम

वी. वीरप्पन और अन्य.

अप्रैल 11, 2007

[डॉ. अरिजीत पसाया टी एंड एस.एच. कपाड़िया, जे.जे.]

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963:

एस 16(सी) - अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा-तत्परता की रक्षा और इच्छा-मुकदमा डिक्री-इसके बाद मुकदमा संपत्ति अलग-अलग बेची गई व्यक्तियों और दायर की गई अपील-हेल्ड: संप्रेषण के बाद एकमात्र प्रश्न होना चाहिए निर्णय यह दिया जाता है कि क्या क्रेता बिना मूल्य के वास्तविक क्रेता था सूचना-तत्परता और इच्छा का प्रश्न प्रासंगिक नहीं है-इसलिए, अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं है.

प्रतिवादी नं. 1 ने समझौते के विशिष्ट पालन के लिए मुकदमा दायर किया उत्तरदाताओं क्रमांक 2 से 9 के विरुद्ध मुकदमा डिक्री किया गया। हालाँकि, प्रतिवादी-प्रतिवादी ने वह जमीन बेच दी जो मुकदमे की विषय वस्तु थी। प्रतिवादी 1 एस ने मुकदमे में फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील दायर की। खरीददार अपील में अपीलकर्ता 6 से 9 के रूप में पक्षकार बनने के लिए एक आवेदन दायर किया। एतत्परता और इच्छा के बचाव पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई। एकल न्यायाधीश ने कहा कि अपीलकर्ताओं के लिए कोई भी मामला उठाने पर कोई रोक नहीं है तत्परता और इच्छा के बचाव को छोड़कर अपील के गुण-दोष के आधार पर जारी किया जाएगा जैसा कि एस के तहत प्रदान किया गया है। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 16 (सी)। डिवीजन बेंच और अपील द्वारा पक्षकार आवेदन की अनुमति दी गई थी गुण-

दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। व्यथित होकर क्रेताओं ने मामला दायर किया वर्तमान अपील।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि याचिका तत्परता से संबंधित है और अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में इच्छा जताई जा सकती है; और जब से खरीददारों ने विक्रेताओं के मुकदमे में कदम रखा, दलील तत्परता और इच्छा को सेवा में लगाया जा सकता है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

आयोजित: 1.1. तत्परता और इच्छा की दलील पर सवाल उठाना एक है एक समझौते से संबंधित अवधारणा. संप्रेषण के बाद, एकमात्र प्रश्न है निर्णय यह है कि क्या क्रेता मूल्य के लिए वास्तविक क्रेता था बिना किसी सूचना के, और वास्तव में तत्परता और इच्छा का प्रश्न ही नहीं है उपयुक्त। अत: विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 का प्रावधान नहीं है लागू. एक बार कन्वेयंस हो जाने पर, अवधारणा अलग होगी और प्राथमिक राहत केवल रद्दीकरण हो सकती है। [पैरा 6) (35-बी-सीजे)

राम अवध (मृत) विधिक प्रतिनिधि द्वारा. और अन्य. बनाम अछैबर दुबे और अन्य, (2000) 2 सेकंड 428, अनुपयुक्त ठहराया गया।

1.2. मौजूदा मामले में, खरीददारों को यह साबित करना था कि वे सच्चे हैं। बिना किसी सूचना के मूल्य के लिए खरीददारों को आश्वस्त करें। तत्परता और इच्छा का पहलू उन्हें कोई राहत नहीं देंगे. [पैरा 8) (35-डी-ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 418 के उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.01.2000 से मद्रास में न्यायपालिका एल.पी.ए. 1999 की संख्या 211. सीए 2001 का क्रमांक 419.

के.के. मणि और के.बी. अपीलकर्ताओं के लिए संदीप.के.के. मणि और के.बी. अपीलकर्ताओं के लिए संदीप।

प्रतिवादियों की ओर से वी. प्रभाकर, वी. सुब्रमणि और रेवती राघवन।

डॉ. अरिजित पसायत, जे. सी.ए.नं. 418 से 2001।

1. यह अपील मद्रास उच्च के फैसले के खिलाफ निर्देशित है अदालत। आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई थी ए.एस.सं. में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया। 796/1987 दिनांक 2.11.1999। यह आदेश उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर पारित किया गया था निवेदन।

2. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

3. उप न्यायालय, मदुरै की फाइल पर ओ.एस. संख्या 247 से 1981 दायर किया गया था वीरप्पन द्वारा, किसी समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए पहला प्रतिवादी बिक्री हेतु दिनांक 23.1.1978 प्रतिवादी 2 से 9 तक को मुकदमे में पक्षकार बनाया गया संपत्ति के मालिक और यह आरोप लगाया गया कि मालिकों ने इसमें प्रवेश किया था उसके साथ एक समझौता किया गया और चूंकि समझौते का पालन नहीं किया गया, इसलिए मुकदमा दायर किया गया। दायर किया गया था, ट्रायल कोर्ट द्वारा डिक्री पारित होने के बाद, प्रतिवादी अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बड़ी मात्रा में संपत्तियां बेचीं, जिनमें शामिल हैं कुछ अन्य व्यक्तियों के पक्ष में मुकदमे की विषय वस्तु जो हैं उपस्थित अपीलकर्ता. इस बीच, प्रतिवादी 1 से 5 ने ए.एस. में अपील दायर की। क्रमांक 796 सन् 1987 के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष ओ.एस. संख्या 247 से 1981 और यहां अपीलकर्ता बाद के खरीदार हैं दायर सी.एम.पी. 1989 के 3707 में स्वयं को 6 से 9 में अपीलकर्ता के रूप में पक्षकार बनाने के लिए इस आधार पर अपील करें कि मूल अपीलकर्ता 1 से 5, पूर्व स्वामी,

पहले प्रतिवादी के साथ मिलीभगत करने की कोशिश कर रहे थे। अपीलकर्ताओं 1 से 5 ने सी.एम.पी. दायर किया। 1990 की संख्या 4388 एक के पक्ष में अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी वापस लेने के लिए चक्रपाणि और सेथुरमन. उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश बर्खास्त सी.एम.पी. 1989 की संख्या 3707 अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई सी.एम.पी. को पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई। क्रमांक 4388 ऑफ 1990 आदेश दिनांक 28.6.1990 द्वारा अपीलकर्ताओं ने एल.पी.ए. दायर किया। क्रमांक 113 सन् 1990 के बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध सी.एम.पी. 1989 का क्रमांक 3707 और इसके विरुद्ध अपील दायर करने की अनुमति भी मांगी सी.एम.पी. को अनुमति देने वाला आदेश 1990 का क्रमांक 4388। दोनों एल.पी.ए. और सी.एम.पी. क्रमांक 9570 से 1990 द्वारा अपील की अनुमति मांगने पर एक सामान्य आदेश द्वारा निपटारा किया गया दिनांक 28.3.1990. एल.पी.ए. 1990 के 113 की अनुमति दी गई और परिणाम के साथ अपीलकर्ताओं को अपील में 6 से 9 अपीलकर्ताओं के रूप में नेतृत्व किया गया था और ए.एस. क्रमांक 796 1987 के मामले को भी गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया गया।

4. उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों का विश्लेषण करने के बाद फैसला सुनाया निम्नलिखित अनुसार:

> "इसलिए, हम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पर कायम हैं और मामले की परिस्थितियों के अनुसार, अपीलकर्ताओं के लिए कोई रोक नहीं है में विचार हेतु अपील के गुण-दोष के आधार पर कोई भी मुद्दा उठाएं प्रदान की गई तत्परता और इच्छा के बचाव को छोड़कर अपील विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 16 (सी) के तहत।

परिणामस्वरूप, तदनुसार अपील का आदेश दिया जाता है। कोई लागत नहीं.नतीजतन, कनेक्टेड सी.एम.पी. बर्खास्त किया जाता है।"

(जोर देने के लिए रेखांकित)

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिका संबंधित है विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सूट में तत्परता और इच्छा को बढ़ाया जा सकता है अनुबंध। राम अवध मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर गहरा भरोसा जताया गया है (मृत) एलआरएस द्वारा। और अन्य. बनाम अछैबर दुबे और अन्य, [2000] 2 एससीसी 428।इसलिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय की दृष्टि में यह उचित नहीं था।

एम.एम.एस. निवेश, मदुरै बनाम वी. वीरप्पन [पसाया टी, जे.)

6. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने इसका समर्थन किया उच्च न्यायालय का निर्णय.

7. तत्परता और इच्छा की दलील पर सवाल उठाना एक प्रासंगिक अवधारणा है एक समझौते के लिए, संप्रेषण के बाद तत्परता और इच्छा का प्रश्न वास्तव में प्रासंगिक नहीं है इसलिए, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 का प्रावधान (संक्षेप में 'अधिनियम') लागू नहीं है गौरतलब है कि फैसला राम में है अवध का मामला (सुप्रा) एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां केवल एक समझौता था। कन्वेयंस के बाद, निर्णय लिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या क्रेता बिना किसी सूचना के मूल्य के लिए एक वास्तविक क्रेता था। वर्तमान में मामले में एकमात्र मुद्दा जिस पर फैसला सुनाया जा सकता है वह यह है कि अपीलकर्ता थे या नहीं बिना किसी सूचना के मूल्य के लिए प्रामाणिक क्रेता। सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता तैयार थे और उनकी इच्छा का वास्तव में कोई परिणाम नहीं है। राम अवध में मामले (सुप्रा) में पूर्ण बिक्री के प्रभाव

का प्रश्न ही नहीं था। इसलिए, उस निर्णय का वर्तमान तक कोई उपयोग नहीं हो सकता है मामला संबंधित है. एक बार कन्वेयंस हो जाए तो अवधारणा अलग होगी और प्राथमिक राहत केवल रद्दीकरण ही हो सकती है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि क्रेता विक्रेता के स्थान पर कदम रखें, तत्परता और इच्छा का प्रश्न सेवा में लगाया जा सकता है. यह दलील स्पष्ट रूप से निरर्थक है क्योंकि खरीददारों को यह साबित करना था कि वे मूल्य के हिसाब से वास्तविक खरीददार हैं बिना सूचना के। तत्परता और तत्परता वाला पहलू कोई राहत नहीं देगा उन्हें। ऐसी स्थिति होने के कारण, अपील बिना योग्यता के है और खारिज की जाती है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

सीए 2001 की संख्या 419

9. सी.ए. की बर्खास्तगी के मद्देनजर. 2001 का क्रमांक 418, किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है इस अपील में पारित किया जाए।

अपील स्वीकार की गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भारती पंवार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।